विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए सिटी बैंक ऑफ अमरीका को अनुमति दिया जाना

1061. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए केवल सिटी बैंक ऑफ अमरीका को ही अनुमति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति उसे कब और किन शर्तों पर दी गई थी ;

(ग) विश्व के उन अन्य विदेशी बैंकों के नाम क्या थे जिन्होंने सिटी बैंक ऑफ अमरीका की तरह भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय करने के लिए अनुमति दिये जाने के लिए अनुरोध किया था और उन्हें अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत में सिटी बैंक ऑफ अमरीका द्वारा रुपयों में किए जाने वाले विनिमय का ब्यौरा क्या है और ब्याज की दर क्या है तथा उक्त बैंक ने ब्याज से कितना निवल लाभ अर्जित किया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन कार्य करने के लिए प्राधिकृत कुल 73 डीलरों में से 24 विदेशी बैंकों में से एक सिटी बैंक ऑफ अमेरिका को अनुमति प्रदान की है ।

(ख) सिटी बैंक (जो पहले फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक था) को विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य करने के लिए मई, 1962 में अनुमति दी गई थी जो कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों, विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल का अनुपालन करने तथा विदेशी मुद्रा की दरों के बारे में मार्गनिर्देशकों तथा विदेशी मुद्रा कारोबार संबंधी लेन-देन करने के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन थी ।

(ग) भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अन्तर्गत बैंक को एक बार लाइसेंस जारी करने के बाद भारत में विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार करने के लिए विदेशी बैंकों से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र को अभी तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है ।

(घ) सिटी बैंक को देश में कार्यरत भारतीय व विदेशी बैंकों के समान ही सभी प्रकार के बैंकिंग संबंधी लेन-देन करने के लिए अनुमति दी गई है । विभिन्न प्रकार के अग्रिमों व जमाराशियों पर ब्याज दर के संबंध में जो अनुदेश सभी बैंकों पर लागू होते हैं वही सिटी बैंक पर भी लागू होते हैं । मार्च, 1989 और 1990 को समाप्त अवधि के संबंध में सिटी बैंक के प्रकाशित तुलन-पत्रों के अनुसार अर्जित ब्याज एवं डिस्काउंट तथा निवल लाभ निम्न प्रकार थे :—

(करोड़ रुपये)

	मार्च, 1989	मार्च, 1990
ब्याज एवं डिस्काउंट	196.05	282.34
निवल लाभ	24.21	31.63

Misuse of Government Vehicles

1062. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps to ensure minimum consumption of petrol by Government vehicles to effect savings in Government spending;

(b) whether steps have also been taken to ensure use of official vehicles on genuine occasions;

(c) whether Government are aware that CRPF jeeps are being misused for bringing the personal staff of high officials in the Home Ministry; and

(d) if so, what steps Government propose to take to effect economy in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Instructions have been issued by the Government that consumption of petrol and diesel in Government vehicles including staff cars should be reduced by 20 per cent compared to the consumption during the year 1989-90.

(b) The Staff Car Rules which regulate the use of staff cars, have the necessary provisions to ensure use of official vehicles for bonafide purpose. Instructions have recently been reiterated to take suitable steps against misuse of Government vehicles/staff cars.

(c) No such instance has come to notice of the Ministry of Home Affairs.

(d) Does not arise.

Profits Earned by Nationalised Banks

1063. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the profit earned by the nationalised banks in the last financial year; and

(b) what steps are being taken to improve the performance of these banks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) The published profits of 19 out of the 20 nationalised banks who have finalised their accounts for the year 1989-90, aggregate to Rs. 239.73 crores.

(b) Government and the Reserve Bank of India (RBI) have taken series of measures to improve the performance and profitability of the public sector banks. These include augmentation of their capital, higher coupon rates on Government Securities, higher return on cash balances maintained with RBI. Banks have been advised by RBI to draw up action plans with a view to improving their operational efficiency. Banks have also been exhorted to take specific measures to maintain their viability and profitability by means of effective business planning and development. Besides, banks have taken certain measures for enhancing productivity and for effecting economy in expenditure etc.

Resource Transfers by Finance Commissions to Kerala

1064. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that while the Seventh Finance Commission had allocated to Kerala 3.70 per cent of the total resource transfer, the Eighth Finance Commission reduced it to 3.27 per cent and the the Ninth Finance Commission has further reduced it to 301 per cent thereby handing out a raw deal to the State of Kerala;

(b) if so, what corrective steps are being taken in this regard;

(c) whether his Ministry has received any memorandum from Kerala in this connection; and

(d) if so, what action has been taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) In percentage terms, the share of Kerala in the total resource transfer was 3.70 per cent, 3.27 per cent and 3.25 per cent respectively under the recommendations of the Seventh, Eighth and Ninth Finance Commissions. The